युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए योजनाएं

—संगीता यादव

युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया 'स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया' का नारा बेहद कारगर साबित हो रहा है। वास्तव में यह कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली अभियान है, जो भारतीय युवाओं के लिए नौकरी के अधिक अवसर प्रदान करेगा। भारत के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री की ओर से चलाए गए इस नए अभियान को लेकर युवाओ में गजब का जोश भी दिखाई पड़ रहा है। इस पहल से देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए योजना बनाई गई है। ये दुनिया भर में अपने देश के युवाओं की प्रतिभा को कारोबार के माध्यम से दिखाने में मदद करेगी।

केंद्र सरकार की ओर से 'स्टार्टअप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' के जरिए देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए जा रहे इस प्रयास का व्यापक स्तर पर असर भी दिखाई पड़ रहा है। भारत दुनिया के उन सबसे युवा देशों में से है जहां 25 वर्ष से कम लोगों की कुल आबादी 54 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में सरकार इस आबादी को काम और कौशलयुक्त बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य के साथ स्टार्टअप और मेक इन इंडिया सरीके तमाम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

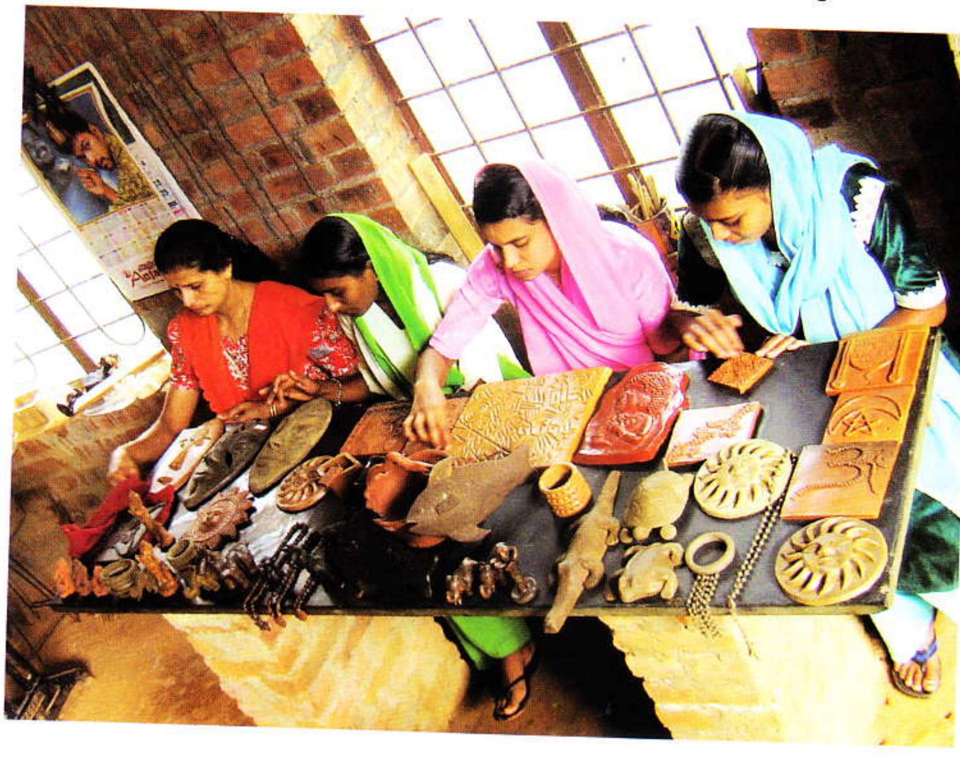

अभी तक दुनिया में व्यापार के माहौल के मामले में भारत का स्थान 135 पर है। ऐसे में सरकार अपने नियमों में खुलापन लाते हुए 50वें नंबर पर आने की कोशिश कर रही है। सरकार की ओर से स्किल डेवेलपमेंट को मूलमंत्र बनाया गया है। साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 16 से 25 प्रतिशत करनी है। इसके जरिए विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या देश में बढ़ी है। एक सर्वे के अनुसार 2030 तक बेरोजगारी लगभग 30 फीसदी होने का अनुमान है। संयुक्त

राष्ट्र के मुताबिक इस समय दुनिया भर में करीब 20 करोड़ बेरोजगार हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। छह वर्ष पूर्व के वित्तीय संकट के बाद अर्थव्यवस्था सुधरने की गति खासी धीमी रही है। इस मामले में सबसे खराब हालत दक्षिण अफ्रीका की है, लेकिन भारत का हाल भी उससे ज्यादा अलग नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कामकाजी उम्र की शुरुआत, यानी 15 से 24 वर्ष के बीच के 20 फीसदी से भी अधिक भारतीय बेरोजगार हैं। 30 से 34 साल की उम्र में बेरोजगारी की दर छह फीसदी है। इस तरह औसतन बेरोजगारी करीब 12 फीसदी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी एक जटिल समस्या बनती जा रही है। शिक्षा और रोजगार के बीच कोई संतुलन ही नहीं बन पा रहा है। यह सब अचानक नहीं हो गया। भारत में बेरोजगारी की समस्या युवाओं के लिए हमेशा परेशानी का सबब बनी रही है। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का फंडा अपनाया गया है।

भारत की आबादी का करीब 70 प्रतिशत गांवों में रहता है जिसके कारण नौकरी करने लायक इन युवाओं की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर महोत्सव होगा। राज्यों के नेतृत्व और केंद्र सरकार के निर्देशन में टीम इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता में अन्य उद्देश्यों के अलावा युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देना शामिल है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इस उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को न सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है बल्कि रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें स्टार्टअप इंडिया को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए अगले चार साल में 10 हजार करोड़ रुपये फंड के बनाने की घोषणा की। इसमें हर साल 2500 करोड़ रुपये के फंड स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप से होने वाला लाभ तीन साल तक कर मुक्त रहेगा।

स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया

केंद्र सरकार की ओर से युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें हुनरमंद बनाना भी जरूरी है। वास्तव में स्टार्टअप का अर्थ देश के उन युवाओं से है जो आर्थिक रूप से खड़े होने की क्षमता रखते हैं, ऐसे में सरकार की ओर से मदद मिलने से उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलेगा और देश के विकास में अपना योगदान भी दे सकेंगे। देश के अत्यधिक कुशल और बहु–प्रतिभाशाली युवा इस अभियान के माध्यम से पूरी तरह से लाभान्वित होंगे और नये रोजगारों का सृजन करने में सक्षम होंगे। ये अभियान मोदी सरकार की भारत को 2022 तक प्रत्येक को घर, बिजली, रोजगार और अन्य बेसिक आवश्यकताओं की उपलब्धता के साथ विकसित देश बनाने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस कार्यक्रम के जरिए विश्व मानचित्र पर भी भारत को उपलब्धि हासिल होगी। अभी तक भारत 4,200 एंटरप्राइजेज के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन से ही स्टार्टअप्स के मामले में पीछे है। दुनियाभर के निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट भारत को स्टार्टअप्स की शुरुआत के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल "स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया" की बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को की थी। उन्होंने वादा किया था कि केंद्र सरकार इस पहल के जरिए युवा उद्यमियों को उद्यमशीलता में शामिल करके बहुत बेहतर भविष्य के लिये प्रोत्साहित करेगी। इसी मंशा के साथ प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की। इसके तहत लगभग 125 लाख बैंकों की शाखाएं युवाओं (कम से कम एक दलित या आदिवासी और एक महिला उद्यमी) को ऋण प्रदान करके प्रोत्साहित करेंगी। ये अभियान भारत में लोगों के लिये नये रोजगारों का निर्माण करेगा। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विनिर्माण इकाइयों के प्रोत्साहन की सुविधा भी है। इस पहल को सफल करने के लिए ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत के लगभग सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी के प्रयासों की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम से भारत को दुनिया की स्टार्टअप राजधानी बनने में सहायता मिलेगी। स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया के शुरु किए जाने के साथ ही इस योजना की पूरी कार्यविधि पेश की जाएगी। एक उच्चस्तरीय अंतर–मंत्रालयी समूह की स्थापना के द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की योजना बनायी गई है, जो नवाचार की देखरेख के साथ ही साथ स्टार्टअप प्रस्तावों के मूल्यांकन से ये सुनिश्चित करेंगे कि वो प्रोत्साहन के योग्य हैं या नहीं।

क्या है "स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया"

वास्तव में यह यह नया अभियान है। इसके जरिए केंद्र सरकार देश के युवाओं की मदद करेगी। ये पहल युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनने का अवसर देगी। स्टार्टअप का अर्थ, देश के युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान करना है जिससे उनकी शुरुआत बेहतर मजबूती के साथ हो ताकि वो भारत में अधिक रोजगार सृजन कर सकें। ये कार्यक्रम स्टार्टअप

को वित्त सहायता से सक्षम बनाने के लिए बड़ी शुरुआत है जिससे कि वो अपने नए अभिनव विचारों को सही दिशा में उपयोग कर सकें।

स्टार्टअप की खास–खास बातें

- इसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू होगा और तीन साल तक कोई जांच अधिकारी नहीं आएगा। तीन साल तक स्टार्टअप पर होने वाले लाभ पर कोई टैक्स नहीं होगा।
- स्टार्टअप के लिए पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपये स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे।
- चार साल तक 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा। पेटेंट फीस में 80 फीसदी की कमी की जाएगी। हैंडहॉल्डिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।
- शेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट दी जाएगी। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत भी की गई है जिसके तहत स्टार्टअप को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। एंटरप्रेन्योर नेटवर्क बनाया जाएगा, स्टार्टअप को सीड कैपिटल देने के साथ कई अन्य सुविधाएं भी होंगी।
- 35 नए इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। बच्चों में इनोवेशन बढ़ाने के लिए इनोवेशन कोर प्रोग्राम शुरू होगा। 5 लाख स्कूलों के 10 लाख बच्चों की पहचान की जाएगी जो इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें।
- अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर स्टार्टअप शुरू करने पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट दी जाएगी।

स्टार्टअप्स एमएसएमई के लिए मानदंडों में ढील

सरकार ने स्टार्टअप्स एमएसएमई के लिए मानदंडों में ढील देने का निर्णय लिया है। निर्णय के मुताबिक, अगर एमएसएमई निर्धारित तकनीकी और गुणवत्ता मानकों के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की डिलीवरी कर सकते हैं, तो उनके लिए पूर्व अनुभव और पूर्व कारोबार से जुड़े मानदंडों में ढील दी जाएगी। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से 20 फीसदी की अनिवार्य सरकारी खरीद में स्टार्टअप एमएसएमई को भी भाग लेने में मदद मिलेगी। यह ढील भारत में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु दी गई है, जो सरकार के एजेंडे में काफी ऊपर है।

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक की शुरुआत करते हुए सभी छोटे उद्यमियों को आसानी से ऋण मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि मुद्रा बैंक की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि छोटे उद्यमियों को व्यापार के लिए ऋण आसानी से मिले और उससे जुड़े कामगारों को रोजी–रोटी की समस्या ना हो। प्रधानमंत्री का मत है कि देश का एक बड़ा तबका छोटे उद्यमों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें बैंक कर्ज देने में कोताही बरतते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। छोटे उद्यमियों को ऋण देने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ेगा और आर्थिक वृद्धि तेज होगी। छोटा–मोटा कारोबार करने वाले कर्जदार ऋण का भुगतान समय पर करते हैं। भारत में बचत करना पुरानी आदत है और इस परंपरा को मजबूती से आगे बढ़ाने तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी से मुद्रा बैंक की कल्पना आई। एनएसएसओ के 2013 के सर्वे के मुताबिक, तकरीबन 5.77 करोड़ लघु व्यासायिक इकाइयां हैं। इनमें से ज्यादातर एकल स्वामित्व के तहत चल रही हैं। इनमें व्यापार, निर्माण, रिटेल और छोटे स्तर की अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इसकी तुलना में संगठित क्षेत्र और बड़ी कंपनियां 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। ऐसे में लघु क्षेत्र में न तो कोई नियामक है और न ही संगठित वित्तीय बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहयोग या सहारा मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक के जरिए दलितों और आदिवासी उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। उद्योग में अधिकतर कुशल श्रमिक दलित समुदायों से हैं। उनमें अपनी सूक्ष्म इकाइयां शुरू करने की संभावना है ।

मुद्रा बैंक के जरिए स्वावलंबी होंगे युवा

मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी है। इसके जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में मुद्रा बैंक की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने एक मुद्रा (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी) बैंक खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिसके पास 20,000 करोड़ रुपये की राशि और 3,000 करोड़ रुपये की साख गारंटी राशि होगी। मुद्रा बैंक बुनियादी तौर पर छोटी इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने की नीति बनाएगा और छोटी इकाइयों को कर्ज देने के लिए फंड उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले यानी शिशु योजना में 50 हजार रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे। जबकि किशोर योजना में 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण देकर

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुद्रा बैंक ठेले और खोमचे वालों को भी ऋण उपलब्ध कराएगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक के प्रमुख उद्देश्य

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक का उद्देश्य है कि सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जदारिता का नियमन और सूक्ष्म वित्तप्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना। इसके जरिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वसहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग दिया जाएगा। कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशानिर्देश उपलब्ध कराना, जिन पर अमल करते हुए व्यापार में नाकामी से बचा जा सके या समय पर उचित कदम उठाए जा सकें। डिफॉल्ट के केस में बकाया पैसे की वसूली के लिए किस स्वीकार्य प्रक्रिया या दिशानिर्देशों का पालन करना है, उसे बनाने में मुद्रा मदद करेगा। छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार किया गया है। शुरुआती दौर में इसके लिए कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें परिवहन, सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं, खाद्य उत्पाद और टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर प्रमुख हैं। इसके साथ ही स्वामित्व/साझेदारी फर्म लघु निर्माण इकाइयों के रूप में कार्यरत दुकानदार, फल–सब्जी विक्रेता, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, ट्रांसपोर्टर, ट्रक ऑपरेटर, हॉकर, सहकारिताएं या व्यक्तियों का निकाय, खाद्य सेवा इकाइयां, मरम्मत करने वाली दुकानें, मशीन ऑपरेटर, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण करने वाले, स्वयंसहायता समूह,10 लाख रुपये तक की वित्तीय अपेक्षा रखने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सेवाप्रदाता तथा पेशेवर व्यवसायों/उद्यम–इकाइयां आदि शामिल होंगे।

मेक इन इंडिया

केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए महत्वाकांक्षी मिशन मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली से की। मेक इन इंडिया को लांच करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ किया कि एफडीआई को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ फर्स्ट डेवलप इंडिया के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे भारत को सिर्फ बाजार के रूप में न देखें बल्कि इसे एक अवसर समझें। प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेशकों को भरोसा दिया है कि विकास और विकासोन्मुख रोजगार भारत सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी की क्रयशक्ति बढ़नी चाहिए क्योंकि इससे मांग बढ़ेगी और निवेशकों को फायदा मिलने के साथ–साथ विकास को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को जितनी तेजी से गरीबी से बाहर निकालकर मध्यम वर्ग में लाया जाएगा, वैश्विक व्यवसाय के लिए उतने ही अधिक अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि 'मेक इन इंडिया' के जरिए लुक ईस्ट अभिव्यक्ति के साथ लिंक वेस्ट को भी निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि स्वच्छ भारत और कचरे से सम्पन्नता मिशन अच्छी आमदनी और बिजनेस का जरिया बन सकते हैं। सरकार ने भी इस तरफ ध्यान देते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी के जारिए भारत के 500 शहरों में बेकार पानी के प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में अपने विज़न का जिक्र किया। ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा रही है कि भविष्य की तस्वीर खुशनुमा हो सकती है।

मेक इन इंडिया की खास बातें

- इस अभियान के अंतर्गत हर साल देश के एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
- इसके अंतर्गत रक्षा क्षेत्र के उपकरण के निर्माण पर भी सरकार का अलग से जोर रहेगा। भविष्य में भारत में ही जेट विमान बनाने की योजना है।
- इस अभियान का लोगो मशीन के कलपुर्जों से बने गिर के

शेर को बनाया गया है, जो आगे बढ़ने को तत्पर दिखता है।

- देश की अगले तीन साल में विश्व बैंक के कारोबार में आसान देशों के सूचकांक में 134 से 50वें स्थान पर आने की कोशिश।
- औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमियों के प्रतिवेदनों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, लाइसेंस की वैद्यता की अवधि तीन साल तक बढ़ा दी गई है।
- कपास, चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अधिक रोजगार की संभावना वाले उद्योगों के आधार पर पांच नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे. इनमें बाकी उद्योगों को भी कर रियायतें देने का प्रस्ताव है।
- रक्षा मंत्रालय 20 उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहा है। रक्षा साजो–सामान के अनेक मामलों के उत्पादन को लाइसेंस से पहले ही छूट दी जा चुकी है।
- सरकार श्रम कानूनों में संशोधन की योजना बना रही है, ताकि काम के घंटों को लचीला बनाया जा सके और प्रशिक्षुओं को लिया जा सके. मजदूरों की कॉलोनी के लिए कर रियायतों का प्रस्ताव है।
- निवेश प्रोत्साहन के लिए सक्रिय एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक टीम काम करेगी जो निवेशकों को ऑनलाइन सूचना मुहैया कराएगी और अधिकारियों के साथ बैठक करवाएगी।
- विशेष रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए शत–प्रतिशत विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए गए हैं. इनकी मंजूरी स्वतः मिल जाएगी।

प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उद्यमशीलता बनाने के लिए मार्जिन मनी के साथ लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों की सहायता करने के लिए एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। पिछले साल इस योजना के तहत मार्जिन मनी के साथ 41,778 परियोजनाओं की सहायता करने के लिए तथा तीन लाख से अधिक व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन के लिए 959.01 करोड़ रुपये खर्च किया गया। इस कार्यक्रम से तमाम युवाओं को रोजगार मिला। युवाओं की रुचि को देखते हुए केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को तेजी से लागू कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2016–17 में इसका न सिर्फ लक्ष्य बढ़ाया गया बल्कि इसमें उपयोग की जाने वाली राशि भी सरकार ने बढ़ा दी है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत मार्जिन मनी के साथ 55,000 परियोजनाओं की सहायता की जाएगी। इससे 4,25,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन होगा। इस पर सरकार की ओर से 1,139 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अ.जा / अजजा / अपिव / अल्पसंख्यकों / महिलाओं / भूतपूर्व सैनिकों / शारीरिक विकलांगों / पूर्वोत्तर क्षेत्र / पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे विशेष श्रेणियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। समसामयिक विषयों पर विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में नियमित लेखन)

पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	एक प्रति का मूल्य	विशेषांक का मूल्य	वार्षिक शुल्क	द्विवार्षिक शुल्क	त्रिवार्षिक शुल्क
1.	योजना	22	30	230	430	610
2.	कुरुक्षेत्र	22	30	230	430	610
3.	आजकल	22	30	230	430	610
4.	बालभारती	15	20	160	300	420
5.	रोजगार समाचार	12	—	530	1000	1400